Historicity Research Journal
Volume 2 | Issue 9 | May 2016

Impact Factor : 0.4521(UIF)
ISSN:- 2393-8900

Research Article

सूखे से पीड़ित भारतः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

रेनू चौहान

असि. प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
एस. बी. डी. कालेज, धामपुर जनपद बिजनौर ।

प्रस्तावना :

सूखे से पीड़ित महाराष्ट्र के देंगनमाल (भारत के सबसे अधिक सूखा पीड़ित इलाकों में से एक है) पर अब समाजशास्त्रियों और सरकार की नजर पड़ी है । वजह है, यहां लगातार पानी की कमी या सूखे के कारण पड़ रहे दुष्प्रभाव । सबसे चौंकाने वाला दुष्प्रभाव है, ऐसे क्षेत्रों में पुरूषों का बहुविवाह प्रथा की ओर मुड़ना । इन इलाकों में एक पुरूष की तीन पत्नियां मिलकर पानी ढूंढती है क्योंकि एक पत्नी की सहायता से पानी ढूंढ़ निकालना

135
लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है शहरी हिस्सों में पानी की मांग । गांवों में 40 लीटर प्रति दिन है।

2011
में भारत में 30 प्रतिशत लोग नलके के माध्यम से पानी का उपयोग कर रहे थे ।

सूखे ने देश के कुछ हिस्सों का समाजशास्त्र ही बदल दिया है। फिर भी धरती की प्यास बुझ नहीं रही, वहीं पानी का दुरूपयोग भी जारी है।

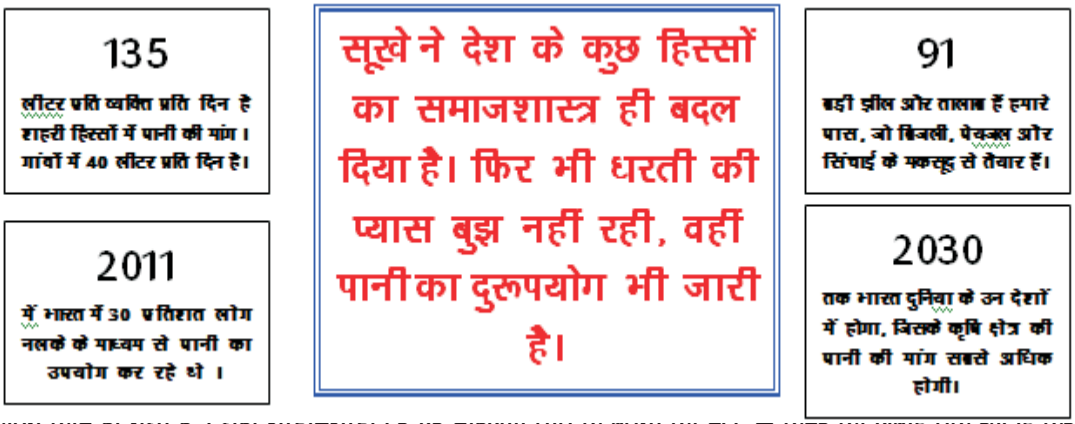

91
बड़ी झील और तालाब हैं हमारे पास, जो बिजली, पेयजल और सिंचाई के मकसद से तैयार हैं।

2030
तक भारत दुनिया के उन देशों में होगा, जिसके कृषि क्षेत्र की पानी की मांग सबसे अधिक होगी।

कठिन काम हो गया है । यहां थोड़ी–थोड़ी दूर पर महिलाएं धातु के बर्तन की मदद से कमर की लंबाई तक खुदाई करती दिखती है । पर अब तेज गरमी में तो उन्हें इस तरह की तीन से चार कोशिश करने के बाद पानी मिल पा रहा है । इसलिए जितनी अधिक पत्नियां, उतना ही अधिक मजदूरी का समान अनुपात । इससे स्थानीय सेक्स अनुपात में गड़बड़ी आई है । शोधकर्ता इन्हें 'वॉटर–वाईफ्स' का नाम दे रहे हैं ।

दूसरी ओर, सूखे से पीड़ित विदर्भ और मराठवाड़ा में, कई बार फसल तबाह होने के कारण, अब पत्नियां परिवार के भरण–पोषण के लिए आगे आने को मजबूर हैं । वे घर से निकलने पर पाबंदी, घूरती निगाहों और तानों को सहती हुई पहली बार घर से निकलकर बाहर काम कर रही हैं । कई तो बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए घर–घर जाकर चूड़ियां बेच रही है । कई पशुओं को बेच रही हैं, जिससे दवाएं खरीद सकें ।

पानी, भारत के लिए ऐसा दुर्लभ स्त्रोत बन गया है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है बल्कि लोगों के लिए भी मुसीबत का पर्याय बन गया है । मानसून के सही तरीके से न आने के कारण एक के बाद एक पड़े सूखे से देश के बड़े हिस्से में पानी की भारी किल्लत हो गई है ।

पश्चिम बंगाल के फरक्का (पूर्वी भारत का सबसे बड़े पॉवर प्लांट) में 13 मार्च को गंगा नदी में पानी का स्तर बेहद कम हो गया था, जिसके कारण उसे कुछ समय के लिए रोक देना पड़ा था ।

लातूर तक रेल डिब्बो की मदद से पानी पहुँचाया जा रहा है । बुंदेलखंड (जिसमें 13 जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक विस्तृत हैं) में तो जिला न्यायधीशों को आदेश दिए गए है कि वे इसे सुनिश्चित करें कि कोई भी पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा किसी और काम के लिए ना करे ।

हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर 91 बड़ी झील और तालाब हैं, जो बिजली, पीने का पानी और सिंचाई के मकसद से तैयार है, इसके बावजूद भी बड़े स्तर पर पानी की कमी हुई है ।

हालांकि पानी की कमी का कारण खराब मानसून को ही माना जाता है । पर इस बार कारण और भी हैं । काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उपलब्ध पानी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ।

हमारे देश में, जहॉ विश्व की आबादी की 16 प्रतिशत जनसंख्या है, जबकि विश्व के कुल पानी का चार प्रतिशत ही हमारे पास है । हमारे देश का सार्वजनिक पानी आपूर्ति सिस्टम चरमराया हुआ है । बड़े शहरों में, ज्यादातर, आपूर्ति, अमीरों को दी जा रही है ।

एक के बाद दूसरे खराब मानसून के कारण ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी तेजी से गिर गई, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मनरेगा भी लड़खड़ा रहा था । धन की कमी की वजह से काम के ज्यादा अवसर पैदा करना या सूखा–ग्रस्त किसानों को वक्त पर भुगतान करना मुश्किल हो गया । ऐसे में धीरे–धीरे देश दशक के सबसे बुरे ग्रामीण संकट में फंसता चला गया ।

तेलंगाना में हर ओर सूखे के कारण चटखी हुई धरती और गुरझाई फसल दिखाई दे रही हैं, फसल बर्बाद होने से दुखी किसान अपने ऊपर बढ़ते कर्ज से इतने हताश और लाचार हैं कि उनके लिए आत्महत्या ही आसान रास्ता नजर आ रहा है । वैसे ठीक–ठीक संख्या बता पाना मुश्किल है, पर 2 जून, 2014 को इस राज्य के गठन के बाद से अब तक यहां 409 किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, तेलंगाना के कृषि मंत्री पोचरम श्री निवास रेड्डी भी हाल ही में स्वीकार कर चुके हैं कि इर रोज कम से कम एक किसान ने आत्महत्या की है, एन जी ओ और किसान संगठनों की मानें तो आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या इसकी कम से कम तीन गुना है ।

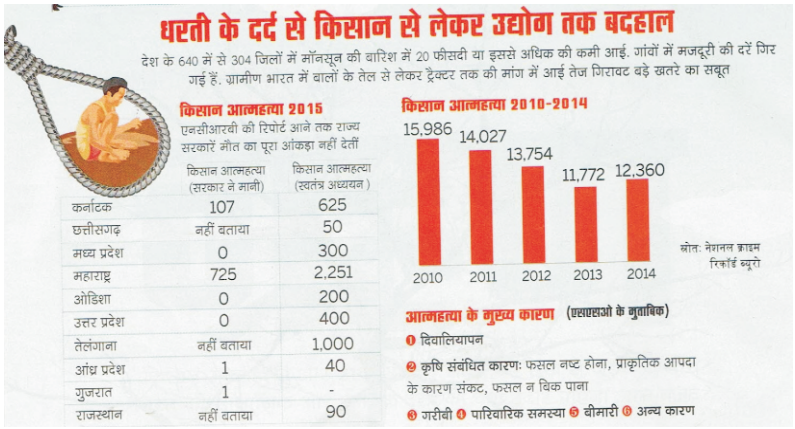

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा से लेकर तेलंगाना और आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक पूरे दक्षिणी पठार में भयानक सूखे के कारण फसल बर्बाद हुई है और बढ़ते कर्ज से परेशान होकर किसानों ने आत्महत्या की है । मराठवाड़ा इलाके को चौथी बार सूखे की मार झेलनी पड़ रही है । यहां अकेले बीड़ जिले में ही अगस्त में 105 से ज्यादा आत्महत्या दर्ज हुई थी । वहीं तेलंगाना और आन्ध्रप्रदेश में लगातार दूसरे साल सूखा पड़ा है । तेलंगाना के मेडक, रंगा रेड्डी, आदिलाबाद, खम्माम, वारंगल और महबूब नगर जिलो में पैसों की तंगी के कारण किसान–आत्महत्या के मामले सामने आए हैं । दक्षिण–पश्चिम मानसून के धोखा देने से सूखे के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं ।

किसान खेती के लिए पानी न ले सके इसलिए मध्य प्रदेश मेंबिजली के खम्भों में सप्लाई रोकी और उत्तर प्रदेश में नहरों पर पहरा बैठाया गया।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बटे बुंदेलखण्ड के किसानों के बीच पानी के बटवारे को लेकर कड़वाहट बढ़ती जा रही है । हालांकि एक बात समान है कि दोनो की ओर के खेतों में फसलें पकने से पहले ही सूख कर झड़ने लगी है और दोनों ही प्रदेशों के किसान मौत को गले लगा रहे हैं ।

2015 में आत्महत्या कर चुके हैं । यह शुरूआती आंकलन है और नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के विस्तृत आंकड़े आने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है । यह संकट इस बार देश के 10 राज्यों – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है । वहीं पंजाब में कपास की फसल को कीड़े खा गए, तो तमिलनाडु में खेती बाढ़ के कारण चौपट हो गई ।

सूखे से शुरू हुआ संकट पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लपेटते हुए अब कस्बों की तरफ बढ़ रहा है । बात अब सिर्फ इतनी भर नहीं है कि किसानों की फसलें तबाह हो गई । अब संकट यह भी है कि फरवरी में ही देश के कई इलाकों में पानी के पानी संकट खड़ा हो गया है और जानवरों के लिए चारा गायब है । हालात देखकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से अब तक किए गए राहत कार्यो का ब्यौरा तलब किया है । मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव कहते हैं, ''बंदेलखण्ड में इस बार सूखा नहीं, अकाल है। पूरे देश के किसानों की हालत इस बार उससे कहीं ज्यादा खराब है । जिसका अनुमान सरकार या शहरी मध्यवर्ग लगा रहा है ।''

अगली बार जब आपको कहीं पानी का नल खुला दिखे या गिलास से एक घूंट पानी पीकर उसे फेंके तो इस तस्वीर को भी जरा याद जरूर करना। यह तस्वीर है महाराष्ट्र के थाने में कासरा गांव की । पानी का कूआं सूख चुका है। सरकारी टैंकर कभी कभी आकर इसमें पानी डाल जाता है। उसके बाद गांव की महिलाएं बच्चे उस पानी को लेने के लिए तपती धूप के बीच कुएं पर डटे रहते हैं। यहां हर शख्स इस बात का मतलब समझता है कि जल ही जीवन है।

पिछले दो साल का गणित देखें तो खरीफ की दो फसलों का खराब मानसून की मार पड़ी, तो 2014–15 की रबी फसल पर अति वृष्टि और इस बार की रवी फसल अल्प वृष्टि का संकट है । चार फसलें चौपट होने के बाद किसान के पास इतनी पूंजी नहीं बचती की वह अपना घर चला सके । ऐसे में दो रास्ते बचते हैं कि या तो वैकल्पिक रोजगार खेजें या फिर बैंक या साहूकार से और कर्ज लें ।

महाराष्ट्र के बीड़ में यह संकट बाल–विवाह की शक्ल ले रहा है । सिर्फ चीनी मिलों के पास काम है और अगर आप जोड़े में काम करते हैं, तो ये कारखाने ज्यादा पैसे देते हैं । नतीजतन, महज 13 साल की बच्चियों की शादियां उनसे एक दो साल बड़े लड़कों के साथ की जा रही है ।

बाल अधिकार कार्यकर्ता तत्वशिल कांबले के मुताबिक, 'पिछले तीन साल के दौरान बाल–विवाह में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी हमने देखी है ।'

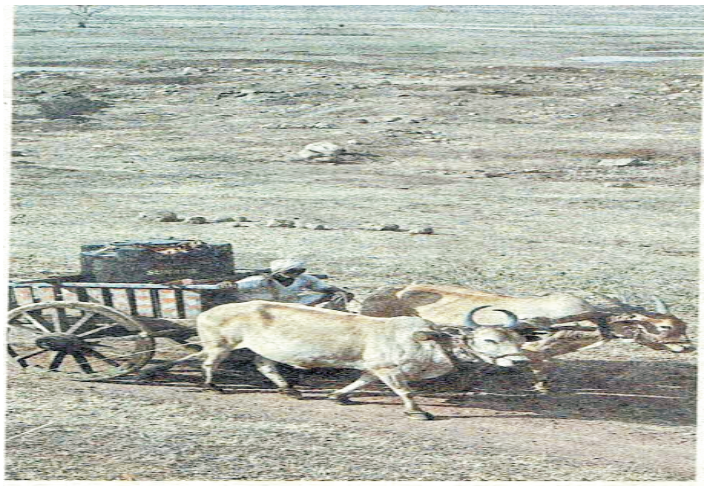

सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के बीड जिले में लगभग सूख चुके डोमरी तालाब से, बैलगाड़ी में पानी की टंकी भरकर ले जाता स्थानीय नागरिक तमछींद्र छिंगोरे
फाइल फोटो

जब कभी सूखा पड़ता है, देश में सिंचाई की मांग जोर पकड़ने लगती है । हालाकिं, अपर्याप्त सिंचाई तंत्र के बावजूद भारत की कुल जल खपत का करीब 80 प्रतिशत कृषि कार्य में ही होता है । जल स्तर के गिरने की अकेली बड़ी वजह धान व गन्ने की खेती है ।

बहरहाल, अनियमित जलापूर्ति, बढ़ता जल–प्रदूषण और उपयोग लायक जल स्त्रोतों में गिरावट के मुकाबले बढ़ती मांग असली समस्या है । और जब मानसून लगातार धोखे दे, तो ये सब मानवीय संकट में तब्दील हो सकते हैं । केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष घनश्याम झा कहते हैं, 'हमारे कृषि क्षेत्र की जल संबंधी मांग काफी बड़ी हैं । पेयजल के लिए तो दस फीसदी से भी कम खपत है । कृषि क्षेत्र की यह मांग चिन्ताजनक है ।' झा की चिंता बेवजह नहीं है । मैकिन्से कन्सल्टिंग के वाटर रिसोर्सेज ग्रुप के मुताबिक, साल 2030 तक भारत दुनिया के उन देशों में से एक होगा, जिसके कृषि क्षेत्र की पानी की मांग सबसे अधिक होगी । अनुमान के मुताबिक, साल 2030 में यह 1,195 अरब क्यूबिक मीटर जल का दोहन करेगा, और इसके लिए उसे अपने मौजूदा उपयोग लायक जल की मात्रा को दोगुना करना होगा ।

सुकून की बात है कि इस बार मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। मौजूदा सूखे की स्थिति तो मानसून आने के बाद शायद खत्म हो जाए, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर बहुत खुशहाली वाली नहीं है । विश्व बैंक व डब्ल्यूएचओ में कंसल्टेंट वसुधा देशमुख का कहना है, 'हालात की बेहतरी के लिए खेती के तरीके में बदलाव लाने, अमीरों से अधिक शुल्क वसूलने, बिजली उत्पादन के लिए अधिकाधिक रीन्यूएबल स्रोत का इस्तेमाल करने और कृषि कार्य में पानी के इस्तेमाल को कम से कम करने वाले उपकरणों को अपनाने की जरूरत है।'

सरकारी प्रयास :

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सूखे की स्थिति पर केन्द्र को आड़े हाथों लिया । कोर्ट ने कहा कि देश के नौ राज्य सूखे से प्रभावित है । केन्द्र सरकार इस पर अपनी आंखे बंद नहीं रख सकती । पीठ ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता भी जताई।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर व न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) 'स्वराज अभियान' की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणीयॉ की शीर्ष कोर्ट ने केन्द्र को गुरूवार तक हलफनामा देकर यह बताने का निर्देश दिया है कि मनरेगा योजना सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है । शीर्ष कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा है कि इन राज्यों में किस तरह फंड मुहैया करा रही है ।

योगेन्द्र यादव के एन जी ओ की तरफ से दायर की गई याचिका में सूखा प्रभावित राज्यों के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने केन्द्र को निर्देश देने की मांग की गई है । राहत एवं पुर्नवास के अन्य उपाय किए जाने के लिए भी केन्द्र को आदेश देने का अनुरोध किया ।

'सूखाग्रस्त 10 राज्यों को 2251 करोड़' :

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केन्द्र ने चालू वित्त वर्ष में सूखा प्रभावित 10 राज्यों को 2551 करोड़ रूपये जारी किए हैं । कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत उपायों की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और केन्द्र उन्हें वित्तीय मदद देता है ।

पूरक प्रश्नों के उत्तर में सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों के पास उपलब्ध

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के समायोजन के बाद 10,275/– करोड़ रूपये की राशि जारी की जानी थी । इसमें से 31 मार्च 2016 को 6055 करोड़ रूपये और आठ अप्रैल को 4220 करोड़ रूपये जारी किए गए ।

सिंह ने कहा कि 2015–16 के दौरान कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, झारखंड और राजस्थान में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता मांगी थी, जो उन्हें दी गई ।

सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने 600 जिलो के लिए, आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं । प्रत्येक जिले के लिए आकस्मिक योजना को उन्नत बनाने और मानसून में देरी से निपटने के तमाम उपाए किए गए हैं ।

सच्चाई सामने आए :–

लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीए शासन के समय महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं के धन का बंदरबांट हुआ है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए ।

उ0प्र0 को 2800 करोड़ :–

सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने उ0प्र0 को 2800 करोड़ रूपये जारी किये गए है। इसमें 2014–15 में 777 करोड़ रूपये और 2015–16 में 1304 करोड़ रूपये जारी किए गए। महाराष्ट्र को 2014–15 के दौरान 1962 करोड़ और 2015–17 के दौरान 3049 करोड़ रूपये जारी हुए ।

निष्कर्ष :–

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम पानी से अच्छी फसल उपजह लेने के लिये कृषकों को तकनीकी सुझाव :–

1. कृषकों को असिंचित क्षेत्रों में पानी कम उपयोग करने वाली फसलों का चयन कर अपने खेतों में उगाना चाहिये । जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, खरीफ की फसल, मसूर, चना, तरा, लाही, जौं आदि । रबी की फसल में मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि जायद की फसलें लगाना चाहिये ।
2. कृषकों को कम पानी की दशा में पानी की सर्ड़िय जल छिड़काव करके पानी की कम मात्रा का सदुपयोग करके फसल उगानी चाहिये ।
3. कृषकों को क्यारी, नाली बनाकर सिंचाई करनी चाहिये ।
4. सिंचाई करने से पहले खेत को समतल करा कर ही सिंचाई की जाये जिससे कम पानी से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और सभी खेत में एक समान सिंचाई की जा सके ।

अन्ततः जल संरक्षण के प्रति हमें बेहद गंभीर होना होगा । यह मुद्दा सिर्फ हमारे राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का है । पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई एक दिन ही नहीं बल्कि जीवन पर्यन्त प्रयास होने चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी को पानी की किल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा ।

सन्दर्भ सूची

1. इंडिया टुडे 30 सितम्बर, 2015, लत नए नशे की, यू0पी0 उत्तराखण्ड विशेष
2. इंडिया टुडे 17 फरवरी, 2016, सदमें में गॉव, यू0पी0 उत्तराखण्ड विशेष

3. इंडिया टुडे 9 मार्च, 2016, नया राश्ट्रवाद, यू0पी0 उत्तराखण्ड विशेष
4. 7 अप्रैल हिन्दुस्तान
5. 7 अप्रैल, दैनिक जागरण
6. 13 अप्रैल, हिन्दुस्तान
7. 13 अप्रैल, अमर उजाला
8. 27 अप्रैल हिन्दुस्तान
9. 28 अप्रैल हिन्दुस्तान
10. 30 अप्रैल हिन्दुस्तान
11. 30 अप्रैल अमर उजाला
12. 1 मई हिन्दुस्तान